



## डिकोडिंग गुड गवर्नेंस

### प्रलिस के लयः

[अटल बहऱरी वाजपेयी](#) और [सुशासन दवऱस](#), [वशऱव बैंक](#), भऱषटऱऱरऱ अनुभूतऱ सूऱकऱंक 2022, [केंदऱरीय लुक शकऱयत नवऱरण और नगऱरऱनी ढरऱणऱली](#), [सूऱऱनऱ कऱ अधकऱर अधनऱयऱड](#), [73वऱँ और 74वऱँ सऱवधऱनकऱ संशुधन](#), [यूनफऱइड ढेमेंटऱस इंटरऱेस](#), [ऱकऱकषी जऱलऱ कऱर्यकऱरड](#), नऱगरकऱ ऱऱरटर

### ढेनऱस के लयः

भऱरत ढें शऱसन वऱवसुथऱ से संबंघतऱ ढरडुख डुदुदे, भऱरत ढें सुशासन से संबंघतऱ ढरडुख ढहल

[सऱरुतः इंडयऱन ँकऱसढरेस](#)

## ऱरऱऱ ढें कऱरुँ?

25 दसऱंबर कुु भऱरत ने ढूरव ढरधऱनडंतऱरी [अटल बहऱरी वाजपेयी](#) कुी जऱयंतऱ के अवसर ढर [सुशासन दवऱस](#) ढनऱयऱ ।

- वऱरुषकऱ तुर ढर ढनऱयऱ जऱने वऱलऱ यह दवऱस शऱसन वऱवसुथऱ तथऱ सरकऱरी ढरकऱरऱऱऱँ ढें उतुतरदऱयतऱव के संबंघ ढें नऱगरकऱ जऱगरूकतऱ बढऱने कऱ ढरऱस करतऱ है ।
- इस अवसर ढर ँकीकृत सरकऱरी ऑनलऱइन ढरशकऱषण (Integrated Government Online Training- iGOT) कऱरडडुगुी ढुलेटऱऱरुड ढर तऱन नई सुवधऱऱँ, डऱई iGOT, बलेंडेड ढुरुगऱरड और कऱरुरेडड ढुरुगऱरड कऱ शुभऱरंभ कऱयऱ गऱयऱ ।

## सुशासन कऱरु है?

- ढरऱऱयः
  - शऱसन वऱवसुथऱ उन ढरकऱरऱऱऱँ, ढरऱणऱलऱरऱँ तथऱ संरऱऱनऱऱँ कुु संदरुभतऱ करतऱ है जनऱके डऱधऱड से संघठनँ, सडऱजँ अथवऱ सडुडुँ कुु नरऱदुेशतऱ, नरऱयंतुरतऱ ँवं ढरबंघतऱ कऱयऱ जऱतऱ है ।
    - सुशासन कुु डुलरुँ के ँक सडुडु के रूड ढें ढरभऱषतऱ कऱयऱ गऱयऱ है जसऱके डऱधऱड से ँकसऱरुवजनकऱ संसुथऱन सऱरुवजनकऱ डऱडलुँ कऱ संऱऱलन करतऱ है तथऱ सऱरुवजनकऱ संसऱधनँ कऱ ढरबंघन इस तरह से करतऱ है कुु डऱनवऱधकऱरुँ, वधऱसऱडडत शऱसन ँवं सडऱज कुी जऱरुरतुँ के अनुरूड हु ।
    - [वशऱव बैंक](#) सुशासन कुु उन ढरंढरऱऱँ तथऱ संसुथऱनँ के संदरुभ ढें ढरभऱषतऱ करतऱ है जनऱके दुवऱरऱ कऱसऱी देश ढें ढरऱधकऱर कऱ ढरडुग कऱयऱ जऱतऱ है । इनडें शऱडलऱ हैः
      - वह ढरकऱरऱऱऱ जसऱके दुवऱरऱ सरकऱरुँ कऱ ऱऱयन, नगऱरऱनी तथऱ ढरतऱसुथऱऱन कऱयऱ जऱतऱ है ।
      - ढरभऱवी नऱतऱरऱँ कुु ढरभऱवी दंग से तैयऱर कर उनुहें कऱरुयऱनुवतऱ करऱने कुी सरकऱर कुी कषडतऱ ।
      - उन संसुथऱनँ के ढरतऱ नऱगरकऱरुँ तथऱ रऱजुड कऱ सडडडऱन कुु उनके डीऱऱ ँरुथकऱर ँवं सऱडऱजकऱर संबंघुँ कुु नरऱयंतुरतऱ करते है ।

सुशासन के डुल सदऱधऱंतः



## वश्वव्यापी शासन संकेतक क्या है?

- वश्व बैंक की वश्वव्यापी शासन संकेतक परयोजना शासन के छह मूलभूत उपायों के आधार पर 200 से अधिक देशों का मूल्यांकन करती है।
- छह संकेतक हैं:
  - अभवियक्ति और दायित्व
  - राजनीतिक स्थरिता और हसिा का अभाव
  - सरकारी प्रभावशीलता
  - नयामक गुणवत्ता
  - [वधि का शासन](#)
  - भ्रष्टाचार पर नयित्रण

## भारत में शासन से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- भ्रष्टाचार और नौकरशाही अक्षमता: [भ्रष्टाचार बोध सूचकांक- 2022](#) में रश्वतखोरी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के बारे में चर्चाओं को उजागर करते हुए भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर था।
- असमानता और सामाजिक बहिष्कार: आर्थिक विकास के बावजूद, अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर बना हुआ है। वर्ष 2022 की ऑक्सफैम रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की 40% से अधिक संपत्ति है, जबकि निम्न स्तरीय 50% के पास सरिफ 3% संपत्ति है। इससे स्वास्थय देखभाल, शक्तिषा और अवसरों तक पहुँच में असमानताएँ बढ़ती हैं।
- नीतियों और योजनाओं का अप्रभावी कार्यान्वयन: कई अच्छे इरादे वाले सरकारी कार्यक्रम खराब नषिपादन के कारण प्रभावित होते हैं, जिससे उनका प्रभाव सीमित हो जाता है।
  - वर्ष 2023 में CAG ने [आयुषमान भारत योजना](#) में अनयिमतिताएँ पाईं, इसके अलावा CAG की एक अन्य रिपोर्ट में [झारखंड में पुरुषों को वधिवा पेंशन के हसत्तांतरण](#) पर प्रकाश डाला गया है।
- अपर्याप्त न्यायिक अवसरचना: भारत के न्यायालय बड़े पैमाने पर लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं, जिससे वविाद समाधान और न्याय तक पहुँच में देरी हो रही है, खासकर हाशयि पर रहने वाले लोगों को।

- वर्ष 2023 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) में 80,000 से अधिक मामले लंबित थे, जिससे कानूनी सहायता तक समय पर पहुँच को लेकर चर्चाएँ बढ़ गईं।
- पर्यावरणीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन: भारत को वायु प्रदूषण, जल की कमी और वनों की कटाई जैसी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। [वर्ष 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट](#) ने पर्यावरणीय नयियों के कमजोर प्रवर्तन को उजागर करते हुए **कई भारतीय शहरों को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों में स्थान दिया है।**
- राजनीतिक ध्रुवीकरण और जवाबदेही का अभाव: बढ़ते पक्षपात और चुनावी लाभ पर ध्यान कभी-कभी भारत में दीर्घकालिक नीति नियोजन और लोक कल्याण पर भारी पड़ जाता है।

## भारत में सुशासन से संबंधित प्रमुख पहल क्या हैं?

- पारदर्शिता और दायित्व:
  - [सूचना का अधिकार अधिनियम \(2005\)](#): यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुँचने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को कम करने का अधिकार देता है।
  - [केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और नगरानी प्रणाली \(CPGRAMS\)](#): सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने और उन पर नज़र रखने के लिये ऑनलाइन मंच।
  - [ई-गवर्नेंस पहल](#): बढ़ी हुई दक्षता और कम मानवीय संपर्क के लिये सरकारी सेवाओं (जैसे, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, संपत्ति पंजीकरण) का डिजिटलीकरण।
  - [सटीक चार्टर](#): सरकारी एजेंसियों द्वारा सेवा मानकों और समय-सीमा के प्रति प्रतिबद्धता, जवाबदेही बढ़ाना।
- नागरिक भागीदारी और सशक्तीकरण:
  - [MyGov प्लेटफॉर्म](#): यह नागरिकों को नीतिगत चर्चाओं में भाग लेने, विचार प्रस्तुत करने और सरकार को प्रतिक्रिया प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
  - [ग्राम सभाएँ](#): ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागी निर्णय लेने के लिये ग्राम-स्तरीय बैठकें।
  - [शिक्षा का अधिकार अधिनियम \(2009\)](#): समुदायों को सशक्त बनाते हुए 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- वक़्दरीकरण और स्थानीय शासन:
  - [73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन](#): स्थानीय लोकतंत्र को बढ़ावा देते हुए वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के साथ पंचायतों (ग्राम परिषदों) तथा नगर पालिकाओं को सशक्त बनाना।
  - [आकांक्षी जिला कार्यक्रम](#): भौगोलिक रूप से वंचित 112 जिलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - [स्मार्ट सटी मशिन](#): बेहतर जीवन के लिये बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी समाधान के साथ 100 शहरों का विकास।
- अन्य पहल:
  - [डिजिटल इंडिया कार्यक्रम](#): इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक व्यापक पहुँच के साथ भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है।
  - [प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण](#): बैंक खातों के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को सब्सिडी और लाभ का हस्तांतरण, रसिद और भ्रष्टाचार को कम करना।
  - [आधार कार्ड](#): नागरिकों के लिये विशिष्ट पहचान प्रणाली, वित्तीय समावेशन और सेवा वितरण को बढ़ावा देना।
  - [दवाला और दवालापन संहिता \(2016\)](#): यह खराब ऋण की समस्या को हल करने और व्यापार पुनरुद्धार की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है।
  - [यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस \(UPI\)](#): भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नगिम (NPCI) द्वारा वक़्दरति त्वरति वास्तविक समय मोबाइल भुगतान प्रणाली।
    - यह एकल मोबाइल एप का उपयोग करके नरिबाध अंतर-बैंक लेन-देन सक्षम बनाता है।

## आगे की राह

- [जनडेटा प्लेटफॉर्म](#): वक़्दरति सेवाओं और नीतिगत निर्णयों में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी के लिये ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा समर्थित एक सुरक्षित डेटा प्लेटफॉर्म बनाए जाने की आवश्यकता।
  - इसमें [स्मार्ट गवर्नेंस डैशबोर्ड](#), विभिन्न सरकारी विभागों के लिये प्रमुख पहल की पारदर्शिता और पहुँच को बढ़ावा देना शामिल होना चाहिये।
- नौकरशाही में सुधार: प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लालफीताशाही को कम करना और सार्वजनिक सेवा के भीतर व्यावसायिकता तथा जवाबदेही को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। [विकास \(वेरिबल एंड इमर्सिवि कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट\)](#) इस दिशा में एक आवश्यक कदम होगा।
- त्वरति न्यायिक सुधार: लंबित मामलों का समाधान करके न्यायालय प्रणाली के भीतर बुनियादी ढाँचे और दक्षता में सुधार करना और सभी के लिये न्याय तक त्वरति पहुँच सुनिश्चित करना। [ई-कोर्ट](#) और [अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग](#) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- [AI-संचालित शिकायत समाधान](#): एक AI संचालित प्रणाली वक़्दरति करना जो सार्वजनिक शिकायतों का विश्लेषण, पैटर्न की पहचान करती है और स्वचालित रूप से उन्हें त्वरति समाधान के लिये संबंधित अधिकारियों को नरिदेशित करती है।

- नागरिक सहभागिता की पुनः कल्पना: शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों की देख-रेख में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समुदाय-आधारित नवाचार प्रयोगशालाएँ स्थापित करना, नागरिकों को सरकारी एजेंसियों के सहयोग से स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान खोजने के लिये सशक्त बनाना।
- भविष्योन्मुखी शिक्षा पाठ्यक्रम: आलोचनात्मक सोच, डिजिटल साक्षरता और डेटा विश्लेषण जैसे कौशल को शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करना, भविष्य की पीढ़ियों को प्रौद्योगिकी-संचालित शासन परदृश्य में सक्रिय भागीदारी के लिये तैयार करना।

इसलिये **भारत को सतत विकास लक्ष्य (SDG) 16: शांति, न्याय और मज़बूत संस्थानों के साथ संरेखित** करते हुए "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के सिद्धांत का पालन करना चाहिये।

## अटल बहारी वाजपेयी:



- 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर, जो अब मध्य प्रदेश का हिस्सा है, में जन्मे अटल बहारी वाजपेयी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनीति में प्रवेश किया।
- 1996 और 1999 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार जनादेश हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने। (वर्तमान में नरेन्द्र मोदी)
  - 9 लोकसभा और 2 राज्यसभा चुनाव जीते, 1994 में भारत के 'सर्वश्रेष्ठ सांसद' का खिताब अर्जित किया।
- 1994 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ और 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभावशीलता और शासन तंत्र में जनसहभागिता अन्यायनाश्रति होती है। भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंध पर चर्चा कीजिये। (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/decoding-good-governance>

